

क्रम संख्या-39

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009-11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2011 ई0

चैत्र 10, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 124/XXXVI(3)/2010/08(1)/2011

देहरादून, 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 29 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) अधिनियम, 2011  
(अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2011)

हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

“उत्तरांचल” के  
स्थान पर  
“उत्तराखण्ड”  
तथा “हिमगिरी  
नभ विश्वविद्यालय  
(यूनिवर्सिटी इन द  
स्काई)” के स्थान  
पर “हिमगिरी जी  
विश्वविद्यालय”  
पढ़ा जाना

2—हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2003) में जहाँ-जहाँ शब्द “उत्तरांचल” आया है, वहाँ-वहाँ वह शब्द “उत्तराखण्ड” तथा जहाँ-जहाँ शब्द “हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई)” आया है, वहाँ-वहाँ वह शब्द “हिमगिरी जी विश्वविद्यालय” रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

राम सिंह,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of “**The Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) (Amendment) Act, 2011**” (Adhiniyam Sankhya 03 of 2011):

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on March 29, 2011.

No. 124/XXXVI(3)/2010/08(1)/2011

Dated Dehradun, March 31, 2011

**NOTIFICATION**

**Miscellaneous**

**THE HIMGIRI NABH VISHWAVIDYALAYA (UNIVERSITY IN THE SKY) (AMENDMENT) ACT, 2011**

( ACT No. 03 of 2011 )

*Further to amend The Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) Act, 2003*

AN

Act

*Be it enacted by the Legislative Assembly in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:--*

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called The Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) (Amendment) Act, 2011

(2) It shall come into force at once.

The words instead of “Uttaranchal” shall be read as “Uttarakhand” and the words “Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky)” shall be read as “Himgiri Zee University” 2. In the Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) Act, 2003 (Act No. 17 of 2003), wherever the word occurs “Uttaranchal” shall be read as “Uttarakhand” and the words occurs “Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky)” shall be read as “Himgiri Zee University”.

By Order,

**RAM SINGH,**

*Principal Secretary.*



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 11 जुलाई, 2003 ई0

आषाढ 20, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 274/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 11 जुलाई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हिमगिरि नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधयेक, 2003 को दिनांक 02 जुलाई, 2003 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 17, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हिमगिरि नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003.

(अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2003)

राज्य में तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा प्रायोजित, हिमगिरि नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) स्थापित करने और उसे निगमित करने एवं उससे संबंधित या अनुभांगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु अध्यादेश संख्या 04, वर्ष 2003 का प्रतिस्थानी यह

## अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है :-

## अध्याय - 1

## प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक  
एवं प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।
- (2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाये

2. जब तब कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-
  - (क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;
  - (ख) 'संघटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;
  - (ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;
  - (घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधियां, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;
  - (च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी आते हैं ;
  - (छ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;
  - (ज) 'विहित' का तात्पर्य 'परिनियमों द्वारा विहित' से है;
  - (झ) किसी संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ प्राचार्य न हों, वहाँ उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

- (ट) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबंध मंडल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो;
- (ठ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;
- (ड) 'परिनियमों' और 'नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावली से है;
- (ढ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;
- (त) 'तालीम रिसर्च फाउन्डेशन' अहमदाबाद, गुजरात, का तात्पर्य विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था से है जो पंजीकृत पूर्त न्यास और साहित्यिक संस्था है तथा गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है।
- (थ) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;
- (द) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तात्पर्य उस संस्थान से है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है।
- (ध) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) से है;
- (न) 'जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई-मेल, इन्टरनेट, परस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;

## अध्याय - 2

### विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

3. (1) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन अहमदाबाद, गुजरात को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
- (2) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, गुजरात, प्रदेश सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे :-
- (क) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के

विश्वविद्यालय  
की स्थापना के  
लिए प्रस्ताव

- (ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;
- (ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार ;
- (घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य ;
- (च) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे - भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख सुविधायें ;
- (छ) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिचय ;
- (ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;
- (झ) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके ;
- (ट) आन्तरिक संसाधनों - विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना ;
- (ठ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा प्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हों, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा ;

(ड) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन ;

(ड) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति तथा ;

(न) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति ;

विश्वविद्यालय  
की स्थापना

4.

(1)

यदि प्रदेश सरकार आवश्यक ऐसी जांच करने के उपरान्त जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं तो तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद को स्थाई विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निदेश देगी।

(2)

स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी।

(3)

विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय वह अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय स्थापना के तीन वर्ष के अन्दर राज्य के तेरह जनपदों में एक-एक अध्ययन केन्द्र स्थापित कर लेगा।

(4)

विश्वविद्यालय कुलाध्यक्ष (विजिटर्स) के अनुमोदन से देश के बाहर भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा।

(5)

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय

उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद किया जा सकता है।

- (6) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि तथा चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।
- (7) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता अनुदान, या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई माँग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को  
वित्तीय सहायता आदि  
के लिए  
हकदार न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र एवं जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

किसी संस्था को  
सम्बद्ध करने की  
शक्ति न होना

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं :-

विश्वविद्यालय  
के उद्देश्य

- (क) विश्वविद्यालय का उद्देश्य मल्टीमीडिया तथा अन्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा पारम्परिक साधनों द्वारा विद्या एवं ज्ञान का प्रसार बढ़ी संख्या में जनता को शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान करना और सामान्यतः सामाजिक, शैक्षणिक कल्याण को प्रोत्साहित करना। देश की पारम्परिक शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देना और ऐसी प्रणालियों में मानदण्डों का निर्धारण।
- (ख) वसुधैव कुटुम्बकम् के अपने आदर्श सूत्र के अनुरूप जाति, धर्म, समुदाय, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समूचे देश एवं विश्व भर में फैली समूची मानवजाति को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शोध, शिक्षण और विस्तार कार्यों के संचालन हेतु पारम्परिक आवासीय एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।
- (ग) यथासम्भव शिक्षा के उच्चतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा विशेषज्ञों एवं पियर ग्रुप द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से इसके लिए निरन्तर प्रयासरत रहने के लिए नवीन, लचीले व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम विकसित और तैयार करना तथा अध्यापन।
- (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित पाठ्यक्रम प्रदान करना।
- (च) विद्या के ऐसे विषयों को शिक्षा, अनुदेश तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिन्हें वह उचित समझे।
- (छ) ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित तथा संचालित करना।

विश्वविद्यालय की  
शक्तियाँ

8. 1. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

- (क) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण एवं मान्यता प्रदान करना जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों।
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं संस्थित और प्रदान करना, जिन्होंने :-
- (अ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या
- (ब) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध-कार्य किया हो,
- (घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना,
- (च) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना,
- (छ) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें,
- (ज) धारा (6) में उल्लिखित दूरस्थ शिक्षा पद्धति, वैकल्पिक शिक्षा पद्धति और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना,
- (झ) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर क्रिया-कलापों की व्यवस्था करना,
- (ट) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में सहाय्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- (ठ) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रयोजनार्थ संदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना।
- (ड) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए छात्र को संस्थित और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना,
- (ढ) आवास का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना और आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना।



- (त) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन,
- (थ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे,
- (द) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके।
- (ध) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना।
- (न) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना,
- (प) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तरांचल राज्य के छात्रों के लिये विशेष व्यवस्था करना,
- (फ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हों या न हों।
- (ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियाँ एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत आते हैं। अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार होगा।
- (भ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ, न्यास की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होंगी।
- (म) फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी.डी., वी.सी.डी. और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना।
- (य) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना।
- (र) ब्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना।
- (ल) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी परन्तु उपधारा (1) के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के

प्रोत्साहन के लिए और ऐसी प्रणालियों में शिक्षण मूल्यांकन तथा शोध कार्यों के मानक निर्धारित करने के लिए ऐसे सभी उपाय करेगा जिन्हें वह उचित समझे। इन गतिविधियों, कार्य सम्पादन के लिए उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जिन्हें परिनिर्णयों में विनिर्दिष्ट किया जाये तथा इनमें महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स को, चाहे वे उसके अधिकार क्षेत्र या उससे बाहर हों, अनुदान के आवंटन और संवितरण की शक्ति भी शामिल है।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों। परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राक्ख्यान करने पर प्रतिबन्ध है।

परन्तु और यह भी कि इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, या अध्ययन केन्द्रों या जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनिर्णयों द्वारा अक्वधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय / प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

### अध्याय - 3

### विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर)

(ख) कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति- कुलपति;

(च) संकायाध्यक्ष;

(छ) कुल सचिव;

(ज) वित्त अधिकारी; और

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनिर्णयों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

12. (1) उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्न शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष यदि उन्नका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधधीन होगा।

13. (1) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन अहमदाबाद, गुजरात के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। तत्पश्चात् तालीम रिसर्च फाउन्डेशन न्यासियों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति नियुक्त करेंगे।
- (2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।
14. (1) कुलाधिपति द्वारा उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों को पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
- (क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति;
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
- (घ) व्यवस्थापक मण्डल के तीन नामनिर्देशिती, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।
- (3) समिति योग्यता के आधार पर उपकुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन सदस्यों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।
- (4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।
- (5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।
- (6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।
- (7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।
15. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाये और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। प्रति-कुलपति
16. संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। संकाय अध्यक्ष
17. (1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी की विहित की जाएँ। कुल सचिव

- (2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।
- (3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।
- (4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मोहर की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।
- वित्त अधिकारी** 18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें।
- अन्य अधिकारी गण** 19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

#### अध्याय - 4

#### विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी** 20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-
- (क) व्यवस्थापक मण्डल;
- (ख) प्रबन्ध मण्डल;
- (ग) विद्या परिषद;
- (घ) वित्त समिति; और
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जाएं।
- व्यवस्थापक मण्डल और उसकी शक्तियाँ** 21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :-
- (अ) कुलाधिपति - अध्यक्ष
- (ब) कुलपति - सदस्य-सचिव
- (स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित एक सचिव
- (द) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, द्वारा नामित पाँच व्यक्ति।
- (य) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित व्यक्ति।
- (र) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित राज्य के तीन प्रख्यात विद्या विद् एवं शिक्षाविद् जिनमें न्यूनतम एक महिला होगी।
- (ल) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विद्याविद् जिनमें न्यूनतम एक महिला होगी।
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-
- (क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन;

- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन;
- (घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावली का संशोधन या निरसन;
- (च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना; और
- (छ) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन, और
- (ज) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं ;

(3) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में न्यूनतम तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

प्रबन्ध मण्डल

- (अ) कुलपति;
  - (ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामित व्यक्ति
  - (स) तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, द्वारा नामित पाँच व्यक्ति
  - (द) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक ;
  - (य) कुलाधिपति द्वारा नामित संकायों के दो संकायाध्यक्ष;
  - (र) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो;
- कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति तथा कुल सचिव प्रबन्ध मण्डल का सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो विहित किये जायें।

23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

विद्या परिषद्

- (अ) कुलपति - सभापति
- (ब) कुल सचिव - सचिव
- (स) ऐसे अन्य सदस्य - जैसा परिनियमों में विहित किया जायें।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन, निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

वित्त समिति

- (अ) कुलपति - सभापति
- (ब) वित्त अधिकारी
- (स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर से निम्न पद का न हो।
- (द) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किया जाये;

- (2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण 25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कर्मवाही का अविधिमान्य न होना 26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

### अध्याय - 5

### परिनियम और नियमावली

परिनियम 27. इस अधिनियमके उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों से संबद्ध किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् हैं :-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य-सम्पादन और ऐसी इकाइयों का गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं,
- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संप्रचालन;
- (ग) कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;
- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें;
- (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;
- (छ) विभागों और संकायों का सृजन, समउत्सादन और उनकी पुनर्संरचना;
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (झ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (ट) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के संबंध में उपबन्ध;
- (ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, तथा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क;
- (ढ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, फीसमाफी, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (त) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया;
- (थ) अन्य मामले जो विहित किये जायें।

परिनियम कैसे बनाए जायेंगे 28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाए गए प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

29. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा। परिनियम संशोधन करने की शक्ति
30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियमों और परिनियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :- नियम एवं परिनियम
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या-संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
- (घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
- (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाये।
31. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गयी नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी। नियमावली कैसे बनायी जायेगी
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।
32. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद् नये या अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी। नियमावली को संशोधित करने की शक्ति

## अध्याय - 6

### प्रकीर्ण

33. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी। कर्मचारियों की सेवा शर्तें
- (2) छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।

- (4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।
- अपील का अधिकार 34. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और जेड कैरियर एकेडमी सेन्टर के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मंडल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा, और उस पर प्रबन्ध मंडल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।
- भविष्य नियमों एवं पेंशन 35. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी भविष्य या पेंशन नियमों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे।
- विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद 36. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।
- समितियों का गठन 37. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, या समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।
- आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता।
- सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण 39. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।
- संक्रमणकालीन उपबन्ध 40. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी-
- (क) प्रथम कुलपति एवं प्रति कुलपति, यदि कोई है, की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा;
- (ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा;
- (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये पद धारण करेगा;
- (घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।



41. (1) विश्वविद्यालय कम से कम एक करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता।
- (2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;
- (3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि, या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा, किन्तु स्थायी विन्यास निधि में से किसी राशि को विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों के लिए अन्तरित नहीं कर सकेगा।
- (4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अनधिक विश्वविद्यालय विकास के लिए उपयोग में लाया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित किया जायेगा।
42. (1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी:-
- (क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;
- (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
- (ग) तालीम रिसर्च फाउण्डेशन, अहमदाबाद द्वारा किये गये सभी अंशदान; और
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।
- (2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा।
43. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी:-
- (क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;
- (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि।
- (ग) तालीम रिसर्च फाउण्डेशन, अहमदाबाद द्वारा किये गये सभी अंशदान;
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और
- (च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
- (2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।
44. धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्याधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

स्थायी विन्यास  
निधि

सामान्य निधि

विकास निधि

निधि का  
अनुरक्षण

- वार्षिक प्रतिवेदन 45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष एवं राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
- लेखा और लेखा-परीक्षा 46. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीआई0ए0आई0) के सदस्य हो।
- (3) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपनी संप्रमाण 31 दिसम्बर से पहले अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष उसे कुलाध्यक्ष एवं राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं एवं लेखा-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बंधनकारी होंगे।
- विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति 47. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प, अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गयी किसी पंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल-सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजी में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो, तो वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।
- विश्वविद्यालय का विघटन 48. (1) यदि तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद, अपने संगठन या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार नभ विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव करता है, तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देगा।
- (2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निदेश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाय, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय परन्तु उसके लिए तालीम रिसर्च

फाउन्डेशन, अहमदाबाद को कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जायेगी।

- (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके, तालीम रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से, और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

49. (1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

कठिनाइयों का निराकरण

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनियम या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

51. श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2003 एवद्वारा निरसित समझा जायेगा।

निरसन

आज्ञा से,

भरोसी लाल,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Hingiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 17 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 2<sup>nd</sup> July, 2003.

No. 274/Vidhayee & Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, July 11, 2003

**HINGIRI NABH VISHWAVIDYALAYA (UNIVERSITY IN THE SKY)  
ACT, 2003  
(Act No. 17 of 2003)**

**AN**

**ACT**

A replacing Act of Ordinance No. 04 of 2003 establish and incorporate an University sponsored by TALEEM Research Foundation, Ahmedabad, Gujarat in the State and provide for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted in the fifty fourth year of the Republic of India as follows :

**CHAPTER – 1  
Preliminary**

**Short title and**

**Commencement**

1. (1) This Act may be called the Hingiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) Act, 2003.
- (2) It shall be deemed to have come into force on the date the Notification is issued by the State Government.

**Definitions**

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires—
  - (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
  - (b) "Constituent College" means a college or institution maintained by the University;
  - (c) "Council for Technical Education" means the All India Council for Technical Education established under section-3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987;
  - (d) "Distance Education System" means the system of imparting education through any means of information technology and communication such as multimedia, broadcasting, telecasting, online over internet, other interactive methods, e-mail, internet, computer, interactive talk back, e-learning, correspondence course, seminar, contact programme or a combination of any two or more of such means;
  - (e) "Employee" means employee appointed by the University; and includes teachers and other staff of the University or of a constituent college;

- (f) "Faculty" means faculty of the University;
- (g) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;
- (h) "Principal" in relation to a constituent college, means the Head of the constituent college and includes, where there is no Principal, the Vice Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;
- (i) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordinating and supervising the work of Study Centres in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management.
- (j) "State" means State of Uttaranchal;
- (k) "Statutes" and "Rules" means, respectively, the Statutes and Rules of the University;
- (l) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognised by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students;
- (m) "TALEEM Research Foundation" means the sponsoring body of the University which is a registered Charitable Trust and Literary Society at Ahmedabad, Gujarat.
- (n) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor/Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a constituent college and institution and includes the Principal of a constituent college, in conformity with the norms prescribed by the U.G.C.
- (o) U.G.C means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956
- (p) "University" means the Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) established under this Act
- (q) "Zed Career Academy Centre" means a centre established, maintained or recognised by the University for the purpose of receiving telecast, e-mail, internet, interactive talk back, conducting training, organize lectures, seminars and workshops, advising, counselling or rendering any other assistance required by the students.

## CHAPTER – II

### The University and its Objects

3. (1) TALEEM Research Foundation shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act
- (2) An application containing the proposal to establish a University shall be made to the State Government by the TALEEM Research Foundation. The proposal shall contain the following particulars, namely:-
- ✓ (a) the objects of the University along with the details of the TALEEM Research Foundation;
- ✓ (b) the extent and status of the University and the availability of land;

**Proposal for the establishment of the University**

- ✓(c) the nature and type of programmes of study and research to be undertaken in the University during a period of the next five years;
- ✓(d) the nature of faculties, courses of study and research proposed to be started;
- ✓(e) the campus development such as buildings, equipment and structural amenities;
- ✓(f) the phased outlays of capital expenditure for a period of the next five years;
- ✓(g) the item-wise recurring expenditure, sources of finance and estimated expenditure for each student;
- ✓(h) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to each source;
- ✓(i) the scheme of generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy and other activities relating to the objects of the University and other anticipated incomes;
- ✓(j) the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebates in fee free ship and scholarship for students belonging to economically weaker sections and the fee structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non resident Indians and students of other nationalities;
- ✓(k) the years of experience and expertise in the concerned discipline at the command of the TALEEM Research Foundation as well as the financial resources;
- ✓(l) the system for selection of students to the courses of study at the University; and
- ✓(m) status of fulfilment of such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

**Establishment  
of University** 4.

- (1) Where the State Government, after such inquiry as it may deem necessary, is satisfied that TALEEM Research Foundation, Ahmedabad has fulfilled the conditions specified in sub - section (2), of Section 3, it may direct the TALEEM Research Foundation, Ahmedabad to establish an Endowment Fund.
- (2) After the establishment of the Endowment Fund, the State Government may, by notification in the Official Gazette, accord sanction for establishment of the University.
- (3) The headquarters of University shall be at Dehradun, Uttaranchal and it may have campuses or Regional Centres, Study Centres and Zed Career Academy Centres at such other places, as may be specified by it from time to time.  
Provided that the University shall establish a Study Centre in each of the thirteen districts of the State within a period of three years of establishment.
- (4) The University may, with the approval of the Visitor, also establish such centres outside the country.
- (5) The Chancellor, the Vice - Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.

- (6) On the establishment of the University under sub-section (2), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the University for the purpose of the University except the properties of TALEEM Research Foundation, Ahmedabad, shall stand transferred to, and vest in, the University.
- (7) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired.
5. The University shall be self-financing and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government. **University not to be entitled to financial Assistance**
6. The University may have Constituent colleges, Regional Centres, Study Centres and Zed Career Academy Centres but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation. **No Power to affiliate any institution**
7. The objectives for which the University is established are as follows – **Objects of the University**
- (a) to advance and disseminate learning and knowledge by multimedia and other information and communication technology and also conventional means, and to provide opportunities for education to a larger segment of the population and to promote the educational well being of the society in general, to encourage the distance education and alternate learning systems in conjunction with the conventional educational pattern of the country and to co-ordinate and determine the standards in such systems.
- (b) to benefit the humanity spread all over the country and the world, without any discrimination on the ground of caste, creed, community, gender and religion according to its motto of *Vasudhaiv Kutumbakam* (World as Family). The University shall, organise its activities in conventional residential and distance mode to carry out research, teaching and extension work.
- (c) to develop, design, and teach innovative, flexible professional and technical courses so as to provide best possible education of the highest academic standards and continue to strive to do so by way of peer group and expert evaluation.
- (d) to offer courses conforming to the prescribed courses recognized by the UGC and AICTE.
- (e) to provide education, instruction and training in such branches of learning as it may deem fit.
- (f) to encourage and carry out fundamental and applied research for the advancement and dissemination of knowledge.
8. (1) The University shall have the following powers, viz :- **Powers of the University**
- (a) to establish, maintain and recognize such Regional Centres and Study Centres as may be determined by the University from time to time in the manner laid down by the statutes.
- (b) to carry out all such other activities as may be necessary or feasible in furtherance of the object of the University.
- (c) to hold examinations for, and to institute grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who-
- (i) have pursued a course of study in the University or in a constituent college or under a distant education system at Regional Centres/Study Centres or Zed Career Academy Centre, or
- (ii) have carried on research in the University or in a constituent college or under a distant education system;

- (d) to confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the statutes/provisions.
- (e) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the Statutes.
- (f) to demand and receive such fees, bills, invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;
- (g) to make provision for the advancement of education in distance and alternate learning systems and other areas mentioned in section 6;
- (h) to make provision for extra curricular activities for students and employees;
- (i) to make appointments of the faculty, officers and employees of the University or a constituent college, Regional Centres, Study Centres and Zed Career Academy Centres.
- (j) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University or a constituent college, or a Regional Centre, Study Centre and Zed Career Academy Centre with the prior permission of TALEEM Research Foundation, Ahmedabad.
- (k) to institute and maintain halls and to recognize places of residence for students of the University or a constituent college.
- (l) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their Code of Conduct;
- (m) to create Academic, Administrative, and support staff and other necessary posts;
- (n) to co-operate and collaborate with other Universities in such a manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (o) to provide distant education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organised;
- (p) to organize and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (q) to determine standards of admission to the University or a constituent college, Regional Centre, Study Centre and Zed Career Academy Centre through specialised committees with the approval of Academic Council.
- (r) to make special provision for students belonging to the State of Uttaranchal for admission in any course of the University or in a constituent college, Regional Centre, Study Centre and Zed Career Academy Centre.
- (s) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
- (t) to prescribe such courses for Bachelor Degree, Post graduate, Doctor of Philosophy, Doctor of Science Degrees and Research which would be covered by UGC and AICTE; but University shall have right to start diplomas, certificates etc. in its own subjects;
- (u) to clearly set apart the academic activities of the University from the activities of the Trust.
- (v) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes, CD, VCD and other software;



- (w) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full or in part) at other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time.
- (x) to raise, collect, subscribe and borrow with the approval of the Governing Body whether on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (y) to enter into, carry out, vary or cancel contracts;
- (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the open university and distance education systems and for the determination of standards of teaching, evaluation and research in such systems, and for the purpose of performing this function, the University shall have such powers, including the power to allocate and disburse grants to Colleges, Regional Centres, Study Centres and Zed Career Academy Centres whether admitted to its privileges or not, or to any other university or institution of higher learning, as may be specified by the Statutes.
9. The University shall be open to all persons irrespective of class, creed or gender.  
 Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission to students of the State of Uttaranchal. Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University or a Constituent college or Regional Centres or Study Centres or Zed Career Academy Centres to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the Statutes.
10. The University will seek accreditation from respective national accreditation bodies.

University  
open to all  
classes, castes,  
creed and  
gender

National  
Accreditation

### CHAPTER - III Officers of the University

11. The following shall be the officers of the University:
- the Visitor;
  - the Chancellor;
  - the Vice - Chancellor;
  - the Pro Vice - Chancellor;
  - the Deans of Faculties;
  - the Registrar;
  - the Finance Officer; and
  - such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.
12. (1) The Governor of Uttaranchal will be the Visitor of the University.  
 (2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.

Officers of the  
University

The Visitor

- (3) The Visitor shall have the following powers namely:-
- (a) To call for any paper or information relating to the affairs of the University.
  - (b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Act, Statutes or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned.
- (4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Visitor.

The Chancellor 13.

- (1) Chairman of TALEEM Research Foundation, Ahmedabad, Gujarat will be the first Chancellor of the University, whose tenure shall be of five years. Thereafter TALEEM Research Foundation, with the prior concurrence of the Visitor, would appoint the Chancellor from amongst its trustees.
- (2) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.

The Vice  
- Chancellor 14.

- (1) The Vice - Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the statutes for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).
- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, viz, :-
  - (a) One person nominated by the Visitor;
  - (b) One person nominated by the Chancellor;
  - (c) the Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
  - (d) three nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the convener of the committee by the Board of Governors.
- (3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice - Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.
- (4) The Vice - Chancellor shall be the Principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice - Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.
- (6) The Vice - Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the rules.
- (7) The Chancellor is empowered to remove the Vice - Chancellor after due enquiry. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice - Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.

15. A Pro-Vice - Chancellor may be appointed by the Vice - Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes. **The Pro-Vice-Chancellor**
16. Deans of faculties shall be appointed by the Vice - Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes. **Deans of Faculties**
17. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. **The Registrar**
- (2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
- (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice - Chancellor.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice - Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.
18. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed. **The Finance Officer**
19. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed. **Other officers**

#### CHAPTER-IV

##### Authorities of the University

20. The following shall be the authorities of the University, namely:- **Authorities of the University**
- (a) The Board of Governors;
- (b) The Board of Management;
- (c) The Academic Council;
- (d) The Finance Committee; and
- (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
21. (1) The Board of Governors shall consist of; **The Board of Governors and its powers**
- (a) the Chancellor - Chairman
- (b) the Vice - Chancellor - Member-Secretary
- (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or a Secretary to the State Government nominated by the State Government.
- (d) Five persons nominated by the TALEEM Research Foundation, Ahmedabad
- (e) A nominee of the U.G.C.
- (f) Three eminent educationists and academicians of the State, out of whom at least one will be a woman, nominated by the Visitor.
- (g) Three academicians out of whom at least one will be a woman nominated by the Chancellor

- (2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely: -
- to lay down policies to be pursued by the University;
  - to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
  - to approve the budget and annual report of the University;
  - to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules;
  - to take decision about voluntary winding up of the University;
  - to approve proposals for submission to the State Government; and
  - to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University.
- (3) The Board of Governors shall, meet at least three times in a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.

**The Board of Management**

22.

- (1) The Board of Management shall consist of,-
- the Vice - Chancellor
  - a nominee of the UGC
  - five persons, nominated by the TALEEM Research Foundation, Ahmedabad
  - two Professors of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year
  - two Deans of the faculties as nominated by the Chancellor.
  - Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government.
- The Vice - Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.
- (2) the powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.

**The Academic Council**

23.

- (1) The Academic Council shall consist of :-
- the Vice- Chancellor - Chairman
  - the Registrar - Secretary
  - such other members as may be prescribed in the Statutes.
- (2) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the rules, the Statutes and the Acts, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

**The Finance Committee**

24.

- (1) The Finance Committee shall consist of,-
- the Vice - Chancellor - Chairman
  - the Finance Officer

- (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government.
- (d) such other members as may be prescribed in the Statutes.
- (2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Rules, Statutes and Acts, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

25. The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Other  
Authorities

26. No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

Proceedings not  
invalidated on  
account of vacanc

### CHAPTER-V Statutes and Rules

27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and staff, as given below:-

Statutes

- (a) the procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
- (b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
- (c) the terms and conditions of appointment of the Vice - Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
- (d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
- (e) the procedure for resolving disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;
- (f) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
- (g) the manner of co-operation with other Universities or institutions of higher learning;
- (h) the procedure for conferment of honorary degrees;
- (i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;
- (j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for Uttaranchal students;
- (k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
- (l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
- (m) procedure for creation and abolition of posts;
- (n) other matters which may be prescribed.

28. (1) The first Statutes framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within three months from the date of receipt of the Statutes give its approval with or without modification.

Statutes how  
made

- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the Statutes within the period specified under Sub-section (1) it shall be deemed to have been approved by the State Government.
- Power to amend the Statutes** 29. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes.
- Rules** 30. Subject to the provisions of this Act, the Rules may Provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such ;
  - (b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;
  - (c) the award of degrees and other academic distinctions;
  - (d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
  - (e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
  - (f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;
  - (g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;
  - (h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;
  - (i) all other matters as may be provided in the Statutes and rules under the Act.
- Rules how made** 31. (1) The Rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modification.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed to have been approved by the State Government.
- Power to amend Rules** 32. The Board of Governors may, with the approval of the State Government, make new or additional rules or amend or repeal the rules,

## CHAPTER-VI

### Miscellaneous

- Conditions of service of employees** 33. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.
- (2) Disciplinary action against the students/employees shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.
- (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

- (4) The decision of the tribunal in such matter shall be final.
- (5) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.
34. Every employee or student of the University or of a constituent college, Regional Centre, Study Centre and Zed Career Academy Centre shall, notwithstanding anything contained in this Act have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any such college, Regional Centre, Study Centre and Zed Career Academy Centre as the case may be, and thereupon the Board of Management may confirm, modify or change the decision appealed against. **Right to appeal**
35. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. **Provident Fund and pension**
36. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final. **Disputes as to constitution of University authorities and bodies**
37. Whether any authority of the University is given power by this Act or the statutes to appoint committees, such committees, shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case thinks fit. **Constitution of Committees**
38. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member. **Filling of casual vacancies**
39. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules. **Protection of action taken in good faith**
40. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the Statutes: - **Transitional provisions**
- (a) the first Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three year;
- (b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;
- (c) the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years.

- (d) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years;

**Permanent  
Endowment Fund**

41. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees one crore which may be increased suo motu but shall not be decreased.
- (2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.
- (3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund. Excepting the dissolution of the University, in no other circumstances can any monies be transferred from corpus of the endowment fund for other purposes.
- (4) Not exceeding 75% of the incomes received from the corpus permanent endowment fund which is mentioned in sub para of this section, shall be used for the purposes of development works of the University. The remaining 25 % shall be reinvested into the permanent endowment fund.

**General fund**

42. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely :-
- (a) all fees which may be charged by the University;
- (b) all sums received from any other source;
- (c) all contributions made by the TALEEM Research Foundation Ahmedabad.
- (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force.
- (2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.

**Development  
fund**

43. (1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely :-
- (a) development fees which may be charged from students;
- (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
- (c) all contributions made by the TALEEM Research Foundation, Ahmedabad;
- (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and
- (e) all incomes received from the permanent endowment fund.
- (2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

**Maintenance  
of fund**

44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.



Annual Report

45. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval.
- (2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.
- (3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to Visitor and the State Government before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.

Account and  
audit

46. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.
- (2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India (I.C.A.I.) every year.
- (3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors well before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.
- (4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government along with its observations thereon before the 31st December each year.
- (5) The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.

Mode of proof  
of University  
record

47. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of an any authority or committee of the university or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Dissolution  
of University

48. (1) If TALEEM Research Foundation, Ahmedabad proposes dissolution of the University in the Sky in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government.
- (2) On identification of mismanagement, mal-administration, indiscipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardships in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management system of University. If the directions are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.

- (3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf. Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the TALEEM Research Foundation.
- (4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with the Council for Technical Education and U.G.C. make such arrangements for administration of the University from the proposed date of dissolution of the University by TALEEM Research Foundation Ahmedabad; and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the Statutes.

Expenditure of  
the University during  
dissolution

49. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over period of its management under section 48 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.

- (2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.

Removal of  
difficulties

50. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:  
Provided that no notification or order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.
- (2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State legislature.

51. Ordinance No. 4 of 2003 Promulgated by the Governor is hereby shall be deemed repealed.

By Order,

BHAROSI LAL,  
Secretary.